नवोन्मेष
रुक्टा (राष्ट्रीय)

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)
(अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से संबद्ध)
website: www.ructarashtriya.org **Email:** info@ructarashtriya.org

सार्ध शती वर्ष
(1863-2013)

केन्द्रीय कार्यालय : देराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर, जयपुर-302004
प्रधान कार्यालय : राजकीय महाविद्यालय, अजमेर-305 001 (राज.)
अध्यक्ष : डॉ. मधुर मोहन रंगा, अजमेर (0145) 2429341, मो. 9414008425
महामंत्री : डॉ. नारायणलाल गुप्ता, अजमेर मो. 9414497042

परिपत्र क्रं. : रुक्टा (रा.)/2013-14/01 आषाढ़ शुक्ल ८ वि. स. २०७० तदनुसार 16 जुलाई, 2013
(सभी इकाई सचिवों एवं सक्रिय सदस्यों को समस्त सदस्यों में प्रसारित करने के अनुरोध सहित प्रेषित)

''विवेकानंद हमारी देश की भावनाओं के मूर्तरूप थे। वे भारत की महत्वाकांक्षाओं एवं उनकी पूर्ति के प्रतीक थे। यह वही भाव धारा है जो हमारे देश के भक्तजनों के भजनों में, हमारे द्रष्टाओं के दर्शन में तथा सर्वसाधारण की प्रार्थनाओं में अभिव्यक्त हुई है। उन्होंने भारत की इस चिरन्तन भावधारा को तात्पर्य एवं वाणी प्रदान की है। – डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

प्रिय महोदय/महोदया,

सादर नमस्कार!

नवीन शैक्षणिक सत्र् (2013-14) के शुभारंभ पर अनेकानेक मंगलकामनाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि यह शैक्षणिक सत्र् हम सबके, समाज एवं राष्ट्र के लिए शुभकारी हो। गत परिपत्र के पश्चात् शिक्षक समस्याओं के संबंध में संगठन की विभिन्न गतिविधियों व उपलब्धियों, सांगठनिक तथा वैचारिक कार्यक्रमों के विवरण एवं आगामी कार्यक्रमों की सूचनाओं सहित यह परिपत्र प्रेषित है।

शिक्षक समस्याओं के संबंध में संगठन की गतिविधियाँ एवं उपलब्धियाँ

1. **यू.जी.सी. एरियर की बकाया चालीस प्रतिशत राशि हेतु आदेश जारी** - निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान ने आदेश क्रमांक एफ-20 (101) आभि./बजट/लेखा/आकाशि/2013-14/345-492 दिनांक 15-7-2013 द्वारा नवीन यू.जी.सी. वेतनमान की 1-1-2006 से 30-9-2009 तक के बकाया एरियर की 40 प्रतिशत राशि के नकद भुगतान के आदेश जारी कर दिये हैं। इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा ने दिनांक 24-6-2013 को ही आदेश क्रमांक प. 1 (3) शिक्षा-4/2009 द्वारा राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों को यू.जी.सी. एरियर की बकाया 40 प्रतिशत राशि हेतु आदेश जारी कर दिये थे। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा यह बकाया राशि वित्तीय वर्ष 2010-11 में निर्गत की जानी थी, जिसका पुर्नभरण केन्द्र सरकार द्वारा होना था। पिछले तीन वर्षों से संगठन ने बकाया राशि निर्गत करने हेतु सरकार पर दबाव बनाया था। सरकार द्वारा एरियर राशि निर्गत नहीं किये जाने के विरोध में रुक्टा (रा.) के आह्वान् पर राज्य भर के शिक्षकों ने विधानसभा पर प्रदर्शन किया था तथा उस समय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से हुई वार्ता में उन्होंने एरियर राशि शीघ्र जारी करने का मंतव्य प्रकट किया था।

2. **अकादमी अवकाश हेतु प्राचार्य अधिकृत** - राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 8 (विविध) अकादमी अवकाश/अकाद/निकाशि/03/II/4582 दिनांक 10-4-2013 के द्वारा राज्य के सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को शिक्षकों द्वारा राज्य की परिसीमा में सेमीनार, संगोष्ठी व कार्यशाला में पत्र वाचन के लिए जाने हेतु अकादमी अवकाश का अधिकार प्रदान कर दिया है। संगठन ने लगातार सरकार पर इस हेतु दबाव बनाया था। संगठन का प्रारंभ से ही स्पष्ट मत रहा है कि अकादमी अवकाश की प्रक्रिया को केन्द्रीकृत कर जटिल बनाना शिक्षकों के शैक्षिक उन्नयन एवं राज्य की उच्च शिक्षा के व्यापक हित में नहीं है। संगठन के दृष्टिकोण को उचित मानकर यह आदेश प्रसारित किये जाने पर संगठन सरकार का आभार व्यक्त करता है।

3. **प्राचार्य एवं उपाचार्य की विभागीय पदोन्नति बैठक सम्पन्न** - राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 1 (8) शिक्षा ग्रुप-3/2013 दिनांक 16-4-2013 के तहत वर्ष 2011-12 व वर्ष 2012-13 की रिक्तियों के लिए प्राचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय/ संयुक्त निदेशक कॉलेज शिक्षा के पद पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति दी गई। दिनांक 25-3-2013 को सम्पन्न पदोन्नति बैठक में वर्ष 2011-12 व वर्ष 2012-13 की रिक्तियों के लिए प्राचार्य स्नातक महाविद्यालय/उपनिदेशक, कॉलेज शिक्षा के पद पर भी वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर शिक्षा अधिकारियों को पदोन्नत किया गया। इसी क्रम में वर्ष 2011-12 व वर्ष 2012-13 की रिक्तियों के लिए उपाचार्य कॉलेज शिक्षा की 4-4-2013 को सम्पन्न विभागीय पदोन्नति बैठक के अनुसार पदोन्नति आदेश प्रसारित किये गये। वर्ष 2010-11 की उपाचार्य एवं स्नातक प्राचार्य की रिव्यू पदोन्नति में आंशिक संशोधन के आदेश भी प्रसारित किये गये। उल्लेखनीय है कि संगठन लगातार लम्बित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की मांग कर रहा था। संगठन ने सरकार से आग्रह किया है कि पदोन्नत अधिकारियों का शीघ्र पदस्थापन किया जाय।

4. **पेंशन हेतु संशोधित आदेश जारी** - राज्य सरकार ने आदेश क्रमांक एफ-12 (2) एफडी/रुल्स/2013 दिनांक 18-6-2013 के द्वारा 2006 से पूर्व सेवानिवृत शिक्षकों की पेंशन संशोधन के आदेश जारी किये हैं। 2006 से पूर्व के पेंशनरों के लिए संशोधित पेंशन आदेश में विसंगतियों का निराकरण करते हुए राज्य सरकार ने आदेश जारी किए है कि सेवानिवृति के समय शिक्षक प्री रिवाइज्ड वेतन श्रृंखला में जिस पद एवं वेतनमान में कार्यरत था, 1-1-2006 से लागू संशोधित वेतनमानों में उसके अनुरूप पे-बैंड में न्यूनतम पे एवं ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत तक 1-1-2006 को देय पेंशन स्टेप अप की जायेगी। इस प्रकार जिन शिक्षकों ने 1-1-2006 से पूर्व चयनित वेतनमान में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली थी, उनकी पेंशन 1-1-2006 को 37400-67000 के वेतनमान में तदनुरूप पे-बैंड के साथ न्यूनतम 23200 पर नियत की जायेगी। इस संबंध में वित्तविभाग के आदेश क्रमांक एफ. 12 (3)एफडी/रूल्स/2008 दिनांक 6-4-2013 के द्वारा 2006 से पूर्व के पेंशनरों को नवीन वेतनमान में पेंशन निधारण 1-9-2006 के स्थान पर 1-1-2006 से करने के आदेश कर दिये थे। उल्लेखनीय है कि संगठन द्वारा इस संबंध में निरन्तर प्रयासरत था तथा इस मांग को लेकर 11 मार्च 2013 को विधानसभा पर प्रदर्शन भी किया गया था। संगठन ने सरकार से मांग की है कि संशोधित पेंशन के अनुरूप 1-1-2006 से एरियर दिया जाय।

5. **मुख्य सचिव श्री सी. के मैथ्यू से शिक्षकों की मांगों पर वार्ता** - 18 अप्रेल, 2013 को संगठन पदाधिकारियों ने मुख्य सचिव श्री सी. के. मैथ्यू से वार्ता कर 11 मार्च, 2013 को विधानसभा प्रदर्शन के

दौरान शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर सरकार को दिये ज्ञापन पर कार्यवाही प्रगति के संबंध में चर्चा की। महाविद्यालय शिक्षकों के पदनाम परिवर्तित किये जाने, यू.जी.सी. एरियर का बकाया 40 प्रतिशत शीघ्र भुगतान करने, पूर्व व अन्यत्र सेवा का लाभ देने, वरिष्ठ व चयनित वेतनमान हेतु संवीक्षा समिति की बैठक आयोजित करने, सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने, राज्य के बाहर सेमिनार संगोष्ठी में पत्रवाचन हेतु अकादमिक अवकाश के अधिकार प्राचार्य को देने, निदेशक (अकादमी) के पद पर वरिष्ठतम शिक्षक की नियुक्ति करने सहित 11 मार्च को विधानसभा प्रदर्शन के दौरान ज्ञापन में दिये गये सभी विषयों पर मुख्य सचिव से चर्चा की गई। श्री मैथ्यू ने सभी विषयों के प्रति सकारात्मक रूख दिखाया। उन्होंने बकाया 40 प्रतिशत एरियर के शीघ्र भुगतान हेतु आश्वस्त किया। शिष्ट मंडल में संगठन अध्यक्ष डॉ. मधुर मोहन रंगा, महामंत्री तथा चित्तौड़ संभाग संगठन मंत्री डॉ. नंदसिंह नरुका सम्मिलित थे।

6. **प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा से भेंट** - 18 अप्रेल को ही संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने शासन सचिवालय में प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा श्री राजीव स्वरूप से भेंट कर शिक्षकों की सभी लम्बित मांगों पर शीघ्र कार्यवाही का अनुरोध किया। उन्होंने सभी विषयों को ध्यानपूर्वक सुना तथा उचित कार्यवाही करने का मंतव्य प्रकट किया। प्रतिनिधि मंडल में संगठन अध्यक्ष, महामंत्री व चित्तौड़ संभाग संगठन मंत्री सम्मिलित थे। इस अवसर पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा शिक्षा के विभिन्न आयामों पर मासिक प्रकाशित होने वाली पत्रिका शैक्षिक मंथन एवं रुक्टा (रा.) के परिपत्र नवोन्मेष की प्रति भी प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा को भेंट की गई।

7. **उपशासन सचिव उच्च शिक्षा से लम्बित विषयों पर चर्चा** - 18 अप्रेल को ही प्रतिनिधि मंडल ने उपशासन सचिव श्री बी. एल. कन्दोई से शिक्षकों की विभिन्न लम्बित समस्याओं पर चर्चा कर संगठन का मत स्पष्ट किया। श्री कन्दोई ने संगठन द्वारा 11 मार्च, 2013 को प्रस्तुत ज्ञापन पर सरकार की तरफ से हो रही कार्यवाही की जानकारी देते हुए सकारात्मक मत प्रकट किया।

8. **मुख्यमंत्रीजी से सी. ए. एस. लाभ उत्तरव्यापी प्रभाव से देने की मांग** - संगठन के द्वारा लम्बे समय से संवीक्षा समिति की बैठक हेतु की जा रही मांग एवं दिनांक 11 मार्च 2013 के विधानसभा प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप राज्य सरकार ने सीनियर एवं सलेक्शन स्केल हेतु 27 मई 2013 को प्रस्ताव प्रपत्र मंगवाने हेतु आदेश तो जारी कर दिये किन्तु इस आदेश में यू.जी.सी., एम.एच.आर.डी. तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की त्रुटिपूर्ण व्याख्या करके शिक्षकों को उनके न्यायोचित लाभ से वंचित करने का प्रयास किया है। इस संबंध में संगठन ने मुख्यमंत्रीजी से विस्तृत पत्र एवं पर्याप्त प्रमाण देकर मांग की है कि सी.ए.एस. लाभ हेतु नवीन नियम उत्तरव्यापी प्रभाव से लागू किये जाये न कि पूर्वव्यापी प्रभाव से। मुख्यमंत्रीजी को ध्यान दिलाया गया है एम.एच.आर.डी. ने 31-12-2008 को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों की वेतन श्रृंखला पुनरीक्षित करने के आदेश जारी किये तथा यू.जी.सी. ने 30-06-2010 को इस संबंध में रेगुलेशन जारी किये। चुंकि रेगुलेशन 30-6-2010 को जारी किये गए, अत: 1-01-2006 से 30-06-2010 के मध्य सी.ए.एस. संबंधी विसंगतियों का समाधान करते हुए 26-08-2010 को एम.एच.आर.डी. ने पूर्व पत्र की निरन्तरता में आदेश क्रमांक 1-36/2009-U-II जारी किये जिसकी अनुपालना में राज्य सरकार के शिक्षा विभाग (ग्रुप-4) ने आदेश क्रमांक प.1 (1) शिक्षा-4/2008 दिनांक 13-4-2011 द्वारा 1-1-2006 से 30-6-2010 के मध्य चयनित वेतनमान में पदोन्नति के

पात्र शिक्षकों को पे-बैंड-3 एवं अकादमिक ग्रेड-पे 8000 रुपये में न्यूनतम 23890 रुपये पर स्थिरीकृत किये जाने तथा जब भी वे तीन वर्ष पूरे करे उन्हें पे-बैंड-4 व अकादमिक ग्रेड पे 9000 रुपये दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की थी। अब राज्य सरकार अपने स्वयं के आदेश की पालना नहीं कर रही है। इसके अतिरिक्त जब आज तक यू.जी.सी. रेगुलेशन के अनुसार सेवा नियमों में कोई परिवर्तन ही नहीं किये गये हैं तो सी.ए.एस. का लाभ पूर्व में जारी एवं वर्तमान में लागू नियमों के अन्तर्गत ही दिया जाना चाहिये। कई राज्यों द्वारा यू.जी.सी. रेगुलेशन को समाहित करते हुए जारी किए गए नवीन वेतनमानों संबंधी आदेश संलग्न करते हुए मुख्यमंत्रीजी ध्यान में यह तथ्य लाया गया है कि इन राज्यों में सी.ए.एस. लाभ हेतु नवीन नियम उत्तरव्यापी प्रभाव से लागू किये गये हैं। मुख्यमंत्रीजी से संगठन द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप कर अधिकारियों को सी.ए.एस. लाभ हेतु संशोधित आदेश उत्तरव्यापी प्रभाव से निकालने के निर्देश देने की मांग की गई है।

9. **चुनाव घोषणा पत्र के अनुरूप पदनाम परिवर्तित किये जाए** - संगठन द्वारा मुख्यमंत्रीजी से एम.एच.आर.डी. एवं यू.जी.सी. के दिशानिर्देशों के अनुसार महाविद्यालय शिक्षकों के पदनाम असिस्टेंट प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर करने की मांग पुनः पुरजोर ढंग से रखी गई है। मुख्यमंत्रीजी का ध्यान कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र 2008 के बिन्दु संख्या 26 की ओर आकर्षित किया गया है। जिसमें स्पष्ट वादा किया गया है कि एम.एच.आर.डी. के निर्णय के अनुरूप चढ्ढा समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन किया जायेगा। एम.एच.आर.डी. ने उच्च शिक्षा में व्याख्याता पदनाम समाप्त कर दिया गया है। किन्तु राज्य में अभी भी पदनाम परिवर्तित नहीं होने से राज्य के शिक्षक देश के अन्य शिक्षकों की तुलना में योग्य होते हुए भी पिछड़ रहे हैं। मुख्यमंत्रीजी से चुनाव घोषणा पत्र में किये गये वादे के अनुरूप निर्णय करवाने की मांग संगठन ने की है।

10. **संयुक्त निदेशक (अकादमिक) से भेंट** - दिनांक 10 जुलाई 2013 को अजमेर में संगठन के एक प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा एवं शिक्षकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर संयुक्त निदेशक (अकादमिक) प्रो. एच. आर. नियाजी से भेंट की। सीनीयर व सलेक्शन स्केल के लिए नए नियम उत्तर व्यापी प्रभाव से लागू करने तथा एपीआई को व्यवहारिक बनाने की मांग का विस्तार से औचित्य संगठन द्वारा प्रो. नियाजी को बताया गया। संगठन ने मांग की कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भांति ही विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षा लेने के लिए कर्त्तव्य अवकाश दिया जाए तथा ग्रीष्मावकाश में प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न करवाने हेतु उपार्जित अवकाश का लाभ दिया जाए। प्रतिनिधि मंडल ने संयुक्त निदेशक से राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की भांति ही अन्य लोक सेवा आयोगों में विषय विशेषज्ञ के रूप में जाने पर कर्तव्य अवकाश देने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल द्वारा संयुक्त निदेशक के ध्यान में लाया गया कि कई महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष में तो प्रवेश नीति के अनुसार 70 विद्यार्थियों के सेक्शन बना दिये जाते हैं किन्तु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में इसका ध्यान नहीं रखा जाता। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता एवं यू.जी.सी. के शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात संबंधी दिशा निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए संगठन ने मांग की कि किसी भी स्थिति में 70 से अधिक विद्यार्थी एक सेक्शन में न हो, ऐसे आदेश प्रसारित किये जाए। प्रतिनिधि मंडल में महामंत्री, प्रधान कार्यालय मंत्री डॉ. एस. के. बिस्सू एवं प्रातीय अंकेक्षक डॉ. सोमकांत भोजक सम्मिलित थे।

11. **वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमानों की पात्रता में पूर्व एवं अन्यत्र की गई सेवा का लाभ दिया जाए :-** संगठन के द्वारा सरकार से निरन्तर विभिन्न पत्रों, ज्ञापनों, भेंटवार्ताओं, धरनों एवं प्रदर्शनों में पूर्व एवं अन्यत्र की गई सेवाओं का लाभ वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमानों की पात्रता हेतु देने की मांग की जाती रही है। किन्तु सरकार द्वारा सकारात्मक कदम नहीं उठाने से त्रस्त शिक्षकों को न्यायालयों में जाना पड़ा है। माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षकों के पक्ष में निर्णय दिये गए, किन्तु न्यायालयों के फैसले के बाद भी हठधर्मिता से सरकार ने पुनः सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी, जिसे भी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार योग्य नहीं मानकर खारिज कर दिया। संगठन ने सरकार से पुनः आग्रह किया है कि लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए एकत्र टैक्स राशि का अपव्यय सरकार की प्रतिष्ठा के प्रश्नों में खर्च न कर शिक्षकों को उनका न्यायोचित अधिकार शीघ्र प्रदान करें।

12. **आर. वी. आर. ई. एस. शिक्षकों को यू.जी.सी. एरियर भुगतान की मांग** - आर. वी. आर. ई. एस. के तहत समायोजित महाविद्यालय शिक्षकों का नवीन यू.जी.सी. वेतनमान का एरियर अभी तक बकाया है। संगठन ने सरकार से मांग की है कि अविलम्ब बजट जारी कर प्रबंध कमेटियों को इस संबंध में निर्देश प्रदान करें कि इन शिक्षकों के बकाया एरियर भुगतान की कार्यवाही प्रारंभ करें।

13. **विश्वविद्यालय प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु कर्तव्य अवकाश दिया जाए** - संगठन ने सरकार से मांग की है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाओं की भांति ही विश्वविद्यालय प्रायोगिक परीक्षाओं में सेवाएं प्रदान करने वाली शिक्षकों को कर्तव्य पर माना जाए। इस संबंध में निदेशक महोदय को पत्र लिख कर उनके ध्यान में यह तथ्य लाया गया है कि प्रायोगिक परीक्षा संपन्न करवाना सेमिनार कार्यशाला एवं अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भांति अकादमिक उन्नयन का कार्य नहीं है। इसीलिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा सम्पन्न करवाने हेतु शिक्षकों की अकादमिक अवकाश के स्थान पर कर्तव्य पर माना गया है। संगठन ने निदेशक से ग्रीष्मावकाश में अन्य महाविद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न करवाने के लिए शिक्षकों को उपार्जित अवकाश का लाभ देने की भी मांग की है।

14. **प्रोटोकॉल के विरुद्ध शिक्षकों की ड्यूटी लगाने का विरोध** - छठी आर्थिक गणना 2013 में कई जिलों में महाविद्यालय शिक्षकों की ड्यूटी सुपरवाईजर कार्य हेतु जिला आर्थिक गणना अधिकारी ने लगाई। संगठन के संज्ञान में आते ही मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव (योजना), निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा संबंधित जिलों के जिला कलेक्टर से इसका कड़ा विरोध दर्ज करवाया गया। अधिकारियों के ध्यान में यह तथ्य लाया गया कि लगाई गई ड्यूटी प्रोटोकॉल तथा पद एवं वेतन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। इस संबंध में योजना आयोग से उप सचिव ने महामंत्री से टेलिफोन पर सम्पर्क कर बताया कि ये ड्यूटियाँ निर्देशों की गलत व्याख्या से लगी है तथा आर्थिक गणना की प्रक्रिया प्रारंभ होने के कारण आदेश निरस्त करने में समय लगेगा, किन्तु भविष्य में ऐसा नहीं हो इसका ध्यान रखा जायगा।

15. **स्वतंत्र कृषि महाविद्यालय खोले जाए** - संगठन द्वारा मुख्यमंत्रीजी, कृषि मंत्रीजी तथा प्रमुख शासन सचिव (कृषि) को पत्र लिख कर राज्य की कृषि शिक्षा, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के व्यापक हित में स्वतंत्र कृषि महाविद्यालय खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ करने की मांग की गई है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कतिपय राजकीय महाविद्यालयों में कृषि विषय एक संकाय के रूप में संचालित है। किन्तु इस संबंध

में ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि कृषि विज्ञान एक विशिष्ट तकनीकी विषय है, इस कारण इसके अध्ययन-अध्यापन हेतु पूर्ण सुविधा युक्त स्वतंत्र महाविद्यालय खोलने की अनुशंसा विभिन्न निरीक्षण दलों द्वारा की जाती रही है। कृषि विज्ञान के स्वतंत्र महाविद्यालय नहीं होने के कारण आई.सी.ए.आर. द्वारा अनुदान भी नहीं मिल पाता है, जिससे शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को अध्ययन-अध्यापन हेतु नवीनतम शोध एवं तकनीकी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। कृषि विज्ञान विषय की परीक्षाएं भी अलग से सेमेस्टर पद्धति द्वारा आयोजित की जाती है, जिनका अन्य संकाय की परीक्षाओं से कोई साम्य नहीं रहता।

16. **शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर दिल्ली में धरना सम्पन्न** - अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर 25 अप्रेल, 2013 को देश के 22 राज्यों से आए प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के शिक्षकों ने शिक्षा एवं शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर संगठन के अध्यक्ष डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल की अध्यक्षता में जंतर-मंतर, नई दिल्ली पर अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। इसमें धरने में 1500 से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया। धरने पर शैक्षिक महासंघ के महामंत्री प्रो. जे. पी. सिंघल ने प्रधानमंत्रीजी को दिये वाले ज्ञापन में सम्मिलित मांगों के औचित्य का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि आज सम्पूर्ण शिक्षा अराजकता के दौर से गुजर रही है, नैतिक व मानवीय मूल्यों का ह्रास हुआ है, भारतीय चिंतन व जीवन मूल्य से शिक्षार्थी दूर जा रहा है, आदर्श जीवन पद्धति पर प्रहार हो रहा है, अत: सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति में परिवर्तन में आवश्यकता है। सरकारों की प्राथमिकता पर शिक्षा नहीं है, वे इस पर पर्याप्त व्यय करने की जिम्मेदारी से बच रही है। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए केन्द्र को सकल घरेलू उत्पाद का 15 प्रतिशत व राज्य को अपने बजट का 30 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करना चाहिये। देश की सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए शिक्षाविदों से युक्त स्वतंत्र व स्वायत्त नियामक आयोग बनना चाहिये। उन्होंने मांग की कि नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा की पालना सुनिश्चित करनी चाहिये तथा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में प्रदान की जानी चाहिये। महाविद्यालय शिक्षकों के पदनाम यू.जी.सी. की अनुशंषानुसार परिवर्तन कर सेवानिवृत्ति उम्र 65 वर्ष करने की मांग का विस्तार से स्पष्टीकरण प्रो. सिंघल ने दिया। जनवरी 2004 से पूर्व की पेंशन योजना बहाल करने, अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों की कोषागार भुगतान व्यवस्था करने, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों व विद्यालयों में रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने, पैरा टीचर, संविदा शिक्षक, अतिथि शिक्षक, शिक्षामित्र, प्रबोधक, अंशकालीन शिक्षक आदि नामों से कार्य करने वाले शिक्षकों की वेतन व सेवा शर्तों में सुधार करने, शिक्षा के बाजारीकरण पर नियंत्रण करने तथा सम्पूर्ण देश में एक समान वेतनमान नीति लागू करने संबंधी मांगों का विस्तृत औचित्य प्रो. सिंघल ने धरना स्थल पर शिक्षकों को संबोधित करते हुए बताया। महामंत्री के संबोधन के बाद विभिन्न राज्यों से आये शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। रूक्टा (रा.) के अध्यक्ष डॉ. मधुर मोहन रंगा ने कहा कि 15 सूत्रीय मांगों को संगठन के पत्रक नवोन्मेष में शामिल किया गया है ताकि सभी शिक्षक महासंघ की गतिविधियों एवं मांगों से भी अवगत रहे। डॉ. रंगा ने कहा संगठन शैक्षिक महासंघ की सभी गतिविधियों व कार्यक्रमों में हमेशा सहयोग प्रदान करेगा। शैक्षिक मंथन के प्रधान सम्पादक प्रो. संतोष पाण्डे ने कहा कि प्रजातंत्र में संख्या बल का महत्त्व है अत: शिक्षकों की अपनी न्यायोचित मांगों के समर्थन में अधिक से अधिक सहभागिता की आवश्यकता है। महासंघ के महामंत्री प्रो. सिंघल ने प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री जी को ज्ञापित ज्ञापन की प्रति भेंट प्रस्तुत कर मांगों पर

अविलम्ब कार्यवाही की मांग की। धरने पर शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष, महामंत्री के अतिरिक्त संगठन मंत्री श्री महेन्द्रजीकपूर, सहसंगठन मंत्री श्री ओमपालजी, उच्च शिक्षा संवर्ग प्रभारी श्री महेन्द्रकुमारजी, अतिरिक्त महामंत्री प्रो. के. बालकृष्ण भट्ट सहित सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी उपस्थित थे। अध्यक्ष डॉ. विमलप्रसाद अग्रवाल ने धरने की सफलता के लिए देश भर से आये शिक्षकों, धरने पर समर्थन देने आए माननीय सांसदों, पत्रकारों, स्थानीय प्रशासन एवं दिल्ली अध्यापक परिषद के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन श्री जगदीश प्रसाद चौहान ने किया। धरने में रुक्टा (रा.) की तरफ से अध्यक्ष, महामंत्री, संगठन मंत्री सहित चालीस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

17. **धरना स्थल पर सांसदों का समर्थन** – शैक्षिक महासंघ की मांगों का कई सांसदों ने धरना स्थल पर उपस्थित होकर समर्थन किया। भाजपा के प्रवक्ता व सांसद श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश के बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में यह प्रासंगिक हो जाता है कि सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति में परिवर्तन किया जाये। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने शिक्षा को अत्यन्त दयनीय स्थिति में पहुँचा दिया है। नियमित रूप से चयनित व पूर्ण वेतन प्राप्त शिक्षकों के स्थान पर संविदा शिक्षकों को नियुक्त किया गया है जो अति अल्प वेतन पर काम करने के लिए विवश है, इसके बावजूद शिक्षकों के लाखों पद रिक्त पड़े हैं। दूसरी ओर सरकार की उपेक्षा तथा शिक्षा अधिकार अधिनियम के कठोर प्रावधानों के कारण एक लाख दस हजार विद्यालय बंद होने की कगार पर है। उन्होंने महासंघ के 15 सूत्रीय मांग पत्र के संबंध में कहा कि संसद में वे शिक्षकों की इन मांगों को जोर-शोर से उठायेंगे। सासंद श्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि शैक्षिक महासंघ द्वारा प्रारम्भ की गई ज्ञान-गंगा का प्रवाह अनवरत चलता रहे, इस हेतु हर संभव सहयोग प्रदान करेंगे। धरना स्थल पर अन्य सांसदों श्री अविनाश राय खन्ना, श्री जे.पी. चढ्ढा, श्री श्रीपाद नायक व श्री हंसराज अहीर ने भी उपस्थित रह कर अपना सहयोग एवं समर्थन व्यक्त किया।

18. **निजी महाविद्यालयों को अनुदान देने के आदेश** – संगठन ने राज्य सरकार से मांग की थी कि अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत जिन शिक्षकों ने सरकारी सेवा में समायोजन का विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं किया है ऐसी संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्रदान कर इन शिक्षकों को पूर्ण वेतन भुगतान के लिए निर्देशित किया जाये। इसी संदर्भ में माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि अनुदानित महाविद्यालयों को अनुदान जारी रखें। शिक्षकों से अनुरोध है कि वे न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में महाविद्यालय प्रशासन से पूर्ण वेतन हेतु आग्रह करें।

सांगठनिक एवं वैचारिक कार्यक्रम

1. **प्रदेश कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग सम्पन्न** – रुक्टा (राष्ट्रीय) का दो दिवसीय प्रदेश कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग 15 एवं 16 मई 2013 को आदर्श विद्या मंदिर, राजा पार्क, जयपुर में सम्पन्न हुआ। अभ्यास वर्ग के उद्घाटन सत्र् में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष डॉ. विमलप्रसादजी अग्रवाल ने संगठन की यात्रा एवं वैचारिक अधिष्ठान विषय पर कार्यकर्ताओं का प्रबोधन किया। डॉ. अग्रवाल ने अभ्यास वर्ग की उपयोगिता एवं आवश्यकता बताते हुए 1956 में रुक्टा के गठन से लेकर वर्तमान स्वरूप तक पहुँचने में आए परिवर्तनों, संघर्षों एवं घटनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शब्द आज हमारी कार्यपद्धति एवं सोच का परिचायक बन चुका है और हम केवल शिक्षक हित ही नहीं वरन् व्यापक

शिक्षा एवं समाज हित में कार्य करते हैं। द्वितीय सत्र में रा. स्व. संघ उत्तर पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक माननीय दुर्गादासजी ने संघ से हमारा संबंध विषय पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने संघ स्थापना की पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि संघ का कार्य केवल व्यक्ति निर्माण करना है किन्तु राष्ट्रीय सोच के व्यक्ति संघ की प्रेरणा से समाज जीवन के हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि 1947 में देश की स्वतंत्रता के पश्चात भी शिक्षा पद्धति में देश की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन नहीं हुए तथा वह मेकॉले मॉडल पर ही चलती रही है। राष्ट्रीय सोच के व्यक्तियों ने इस बारे में विचार करना प्रारंभ किया तथा शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों को लेकर विद्या भारती, विद्यार्थी परिषद्, शिक्षण मंडल एवं शैक्षिक महासंघ जैसे संगठन प्रारंभ हुए। अलग-अलग संगठनों के कार्य क्षेत्र अलग-अलग है किन्तु एक ही व्यापक उद्देश्य भारत माता की जय को लेकर सभी कार्य कर रहे है। उनका कहना था कि हमारी कार्यशैली में आपस में विश्वास, प्रेम, भाईचारा है, हम आपस में प्रतिस्पर्धी नहीं वरन् परिपूरक है। तृतीय सत्र में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के महामंत्री प्रो. जे. पी. सिंघल ने शिक्षक संगठन में कार्य करते समय आने वाली कठिनाईयाँ एवं समाधान विषय पर कार्यकर्ताओं की शंकाओं का समाधान किया। चतुर्थ सत्र में कार्यकर्ता कैसा हो विषय पर संभागियों ने अपने विचार रखे। सत्र् में मार्गदर्शन करते हुए माननीय दुर्गादासजी ने कहा कि कार्यकर्ता को लगातार आत्म निरीक्षण करते रहना चाहिए। स्वयं का आदर्श प्रस्तुत कर उसे कार्य विस्तार का माध्यम बनना चाहिए। पंचम सत्र् में महामंत्री डॉ. नारायण लाल गुप्ता ने संगठन की वार्षिक कार्ययोजना को कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा तथा अध्यक्ष डॉ. मधुर मोहन रंगा ने संगठन की गतिविधियों एवं उपलब्धियों के बारे में बताया।

षष्ठम् सत्र् में पुनरुत्थान ट्रस्ट अहमदाबाद की निदेशिका ताई इंदुमतिजी काटदरे ने भारतीय शिक्षा की चुनौतियाँ एवं समाधान विषय पर विचारोत्तेजक व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि 1813 में इण्डिया एजुकेशन एक्ट भारत की शिक्षा एवं सिद्धान्तों को गलत साबित कर उन्हें समाप्त करने के लिए बनाया गया। 1935 में मैकॉले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की जिसमें 1947 के बाद भी कोई व्यापक परिवर्तन नहीं हुआ है। उनका कहना था कि 1947 में मिली स्वतंत्रता तकनीकी स्वतंत्रता है, ज्ञान के क्षेत्र में हम अभी भी स्वतंत्र नहीं हुए है। ताई ने कहा कि शासन की मान्यता एवं शासन का अनुदान शिक्षा को शासन के अधीन बनाने के प्रमुख कारक है। उन्होंने आह्वान किया कि यदि इस स्थिति में परिवर्तन करना है तो दीर्घ कालीन, सुव्यवस्थित योजना बनाकर कठोर उपचार करना होगा। सप्तम् सत्र् मेंअखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के संगठन मंत्री माननीय महेन्द्रजी कपूर ने समय समर्पण, करणीय कार्य एवं कार्ययोजना क्रियान्वयन विषय पर संभागियों से चर्चात्मक संवाद किया। उन्होंने स्थानीय इकाई, विभाग, संभाग एवं प्रदेश स्तर पर करणीय कार्यों को रेखांकित करते हुए समय समर्पण कर सुव्यवस्थित कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षक संगठन में केवल अपने तक सीमित रह कर ही नहीं वरन् व्यापक राष्ट्रहित के लक्ष्य को लेकर अपने क्षेत्र में कार्य करना है। समारोप सत्र् में रा. स्व. संघ उत्तर पश्चिम क्षेत्र के प्रचारक प्रमुख माननीय नंदलालजी ने कहा कि केवल एकत्र आने से ही वायुमंडल में दिव्य ऊर्जा का प्रकटीकरण होता है। सामूहिक चिंतन एवं सामूहिक मंथन से दिव्य सत्व निकलता है। संगठन के साथ निरन्तर चलने से अंतत: परिणाम निकलता ही है। उन्होंने पाथेय देते हुए कहा कि समझी जानी बातों का पुन: स्मरण, समीक्षा करके एवं व्यवहारिक कार्य योजना बनाकर आगे बढ़ते जाएंगे तो

निश्चय ही पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति होगी। समारोप सत्र में कार्यकर्ताओं का प्रबोधन करते हुए ताई इन्दुमतिजी ने कहा कि यदि राज्य व्यवस्था, समाज व्यवस्था, अर्थ व्यवस्था एवं शिक्षा व्यवस्था ठीक हुई तो ही देश की रक्षा हो सकती है। उनका कहना था कि पश्चिम के ज्ञान को अपने साथ समरस बनाने के लिए हमारी ताकत बढ़ानी पड़ेगी, हमें अपना संदर्भ ग्रंथालय एवं शोधकर्ताओं का संच विकसित करना होगा। उनका कहना था कि हमारी रगों में आज भी भारतीय रक्त है, हृदय में आज भी भारत है, केवल अज्ञान को अनावृत्त कर भारत का ध्यान करने की जरूरत है। यदि मन से योजना बनाकर लगे तो अगले 20 वर्षों में हम लक्ष्यानुकूल परिवर्तन पा सकते हैं। अंत में संगठन के अध्यक्ष डॉ. मधुर मोहन रंगा ने सभी का आभार ज्ञापित किया। अभ्यास वर्ग में प्रदेश भर के चुने हुए 67 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

2. **प्रांतीय कार्यकारिणी बैठक सम्पन्न** - रुक्टा (रा.) की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक संगठन के अध्यक्ष डॉ. मधुर मोहन रंगा की अध्यक्षता में दिनांक 14 मई 2013 को आदर्श विद्या मंदिर, राजा पार्क, जयपुर में सम्पन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम महामंत्री ने पूर्व कार्यकारिणी बैठक की कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। महामंत्री ने गत बैठक के पश्चात् संगठन की गतिविधियों का वृत्त प्रस्तुत किया। मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उपशासन सचिव से भेंट वार्ता, विभिन्न समस्याओं पर मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री एवं अन्य अधिकारियों को लिखे गए पत्र, 11 मार्च 2013 को संपन्न विधानसभा प्रदर्शन से संबंधित विस्तृत जानकारी महामंत्री द्वारा दी गई। इसके बाद सन् 2012-13 की वार्षिक योजना की समीक्षा की गई। सदस्यता में हुई वृद्धि हेतु सदस्यता अभियान पर संतोष व्यक्त किया गया तथा इस वर्ष भी जुलाई माह में ही सदस्यता सम्पन्न करने का निर्णय लिया गया। कार्यकारिणी ने पिछले वर्ष सदस्यता अभियान में रही कतिपय कमियों को इस वर्ष दूर करने का निर्णय लिया तथा इस वर्ष की वार्षिक योजना को अंतिम रूप दिया। वार्षिक योजना में जुलाई मास में सदस्यता अभियान, अगस्त में कार्यकारिणी बैठक, सितम्बर-अक्टूबर में विभागीय सम्मेलन एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी, नवम्बर में कार्यकारिणी बैठक, दिसम्बर-जनवरी में प्रदेश अधिवेशन, जनवरी में कर्तव्य बोध दिवस, फरवरी में महिला सम्मेलन, मार्च में कार्यकारिणी बैठक, अप्रेल में नवसंवत्सर कार्यक्रम तथा मई-जून में अभ्यास वर्ग सम्मिलित किये गए। कार्यकारिणी बैठक में शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष डॉ. विमल प्रसाद जी अग्रवाल, महामंत्री प्रो. जे.पी. सिंघल तथा संगठन मंत्री श्री महेन्द्रजी कपूर का मार्गदर्शन रहा। अध्यक्ष जी को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

3. **शैक्षिक महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक सम्पन्न** - अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की दो दिवसीय कार्यकारिणी बैठक महासंघ के अध्यक्ष डॉ. विमल प्रसाद जी अग्रवाल की अध्यक्षता में जमशेदपुर (झारखण्ड) में दिनांक 8-9 जून 2013 को सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम महासंघ के महामंत्री प्रो. जे. पी. सिंघल द्वारा पूर्व कार्यकारिणी बैठक की कार्यवाही का विवरण एवं कोषाध्यक्ष श्री बजरंगजी मजेजी द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के अंकेक्षित आय-व्यय खातों का विवरण सदन के समक्ष रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। बैठक में संगठनशः कार्यवृत्त रखे गए तथा 25 अप्रेल 2013 को दिल्ली में सम्पन्न धरने की समीक्षा की गई। वार्षिक सदस्यता अभियान के महत्व को रेखांकित करते हुए संगठन मंत्री महेन्द्रजी कपूर ने गहन चर्चा की। बैठक में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के

प्रतिनिधियों ने अलग-अलग बैठक कर अपने वर्ग के शिक्षकों की समस्याओं पर विचार किया। उच्च शिक्षा संवर्ग की बैठक में ए.पी.आई. व्यवस्था में खामियाँ, पदनाम नहीं देने, नेट की अनिवार्यता, पीएच.डी. का लाभ नहीं देने, उच्च शिक्षा संस्थानों में पद रिक्त होने जैसी समस्याओं पर चिंतन मनन किया गया। उच्च शिक्षा संवर्ग का सम्मेलन दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में एम. एस. विश्वविद्यालय, बडोदरा में करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। रा. स्व. संघ के अखिल भारतीय सह सम्पर्क प्रमुख मा. अरुण कुमारजी ने महासंघ द्वारा प्रकाशित पुस्तक ''जम्मू कश्मीर: तथ्य एवं सत्य'' का विमोचन किया तथा जम्मू कश्मीर के सच को विचारोत्तेजक व्याख्यान के द्वारा शिक्षकों के समक्ष रखा। बैठक में इस सत्र् में गुरु पूर्णिमा से गुरु वंदन कार्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। कार्यकारिणी बैठक में संगठन की ओर से अध्यक्ष एवं महामंत्री सहित पाँच पदाधिकारियों ने भाग लिया।

4. **नवसंवत्सर समारोह पूर्वक मनाया गया** - भीलवाड़ा, अजमेर, बून्दी, भरतपुर, अलवर खेतड़ी सहित रुक्टा (रा.) की विभिन्न इकाईयों द्वारा भारतीय नव वर्ष विक्रम संवत् 2070 समारोह पूर्वक मनाया गया। 7 अप्रेल, 2013 को भीलवाड़ा जिले के राजकीय व गैर राजकीय महाविद्यालय की रुक्टा (रा.) इकाईयों द्वारा संयुक्त रूप से संगोष्ठी का आयोजन किया गया। स्थानीय विधायक श्री बिट्ठलशंकर अवस्थी द्वारा भारत माँ के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। संगठन अध्यक्ष डॉ. मधुर मोहन रंगा ने इस अवसर पर कहा कि वर्ष प्रतिपदा से ही कालगणना प्रारंभ होती है सृष्टि का सृजन भी इसी दिन से हुआ था। हमारी कालगणना खगोल शास्त्रीय सिद्धान्तों पर आधारित है व आज भी प्रासंगिक है। इससे पूर्व डॉ. सावन जाँगीड़ ने अतिथियों का परिचय कराया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. हेमन्द्र व्यास ने किया तथा धन्यवाद डॉ. कश्मीर भट्ट ने दिया। कार्यक्रम में महामंत्री, संयुक्त मंत्री डॉ. गंगाश्याम गुर्जर व डॉ. श्यामसुन्दर भट्ट सहित भीलवाड़ा जिले के लगभग 65 व्याख्याता उपस्थित थे। 10 अप्रेल 2013 को रुक्टा (रा.) की राजकीय महाविद्यालय अजमेर इकाई द्वारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के तत्वावधान में नव संवत्सर पर संगोष्ठी आयोजित की गई। सर्वप्रथम संगठन अध्यक्ष ने शैक्षिक महासंघ का परिचय कराया। मुख्य वक्ता शिक्षाविद् श्री हनुमानसिंह राठौड़ ने भारतीय कालगणना का वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि हमारी कालगणना से ब्रह्माण्ड की आयु का ठीक वही आकलन आता है जो बिग बैंग सिद्धान्त से आता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया कि प्राचीन भारतीय साहित्य में आइन्सटीन की काल सापेक्षिकता सिद्धान्त के स्पष्ट प्रमाण हैं। कार्यक्रम का संचालन डॉ. सोमकांत भोजक ने किया। वर्ष प्रतिपदा के दिन रुक्टा (रा.) की विभिन्न इकाईयों द्वारा चौराहों पर एवं महाविद्यालय में सभी को तिलक लगाकर एवं प्रसाद वितरित कर शुभकामनाएं दी गई।

5. **वर्तमान शिक्षा तंत्र में शिक्षक की भूमिका विषय पर संगोष्ठी सम्पन्न** - अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के तत्वावधान में रुक्टा (रा.) की राजकीय महाविद्यालय, अजमेर इकाई द्वारा दिनांक 8 जुलाई 2013 को ''वर्तमान शिक्षा तंत्र में शिक्षक की भूमिका'' विषय पर शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल में इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग के पूर्व प्रोफेसर एवं प्रज्ञा भारती के राष्ट्रीय संयोजक प्रो. सदानंद सप्रे ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों में राष्ट्र गौरव के संस्कार विकसित कर भारत की सर्वांगीण उन्नति का माध्यम बन सकता है। प्रो. सप्रे ने कहा कि आज तंत्र में खराबी की बात सभी करते हैं किन्तु इसी तंत्र में रहते हुए शिक्षक स्वयं के उदाहरण से सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। उन्होंने उपस्थित शिक्षकों से आह्वान

किया कि विज्ञान, कला एवं वाणिज्य सहित ज्ञान के समस्त क्षेत्रों में मौलिक भारतीय चिंतन पर शोध एवं अध्ययन करना वर्तमान समय की बड़ी आवश्यकता है। यदि शिक्षक विद्यार्थी का सहयोगी बनकर उसका प्रेरणा स्त्रोत बने तो उसकी बातों का अद्‌भुत प्रभाव विद्यार्थी के जीवन पर होता है। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य डॉ. परमेन्द्र दशोरा ने कहा कि शिक्षण कार्य को पेशे के रूप में चुनने पर शिक्षक को गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। उनका कहना था कि शिक्षक कार्य मात्र आजीविका कमाने का साधन नहीं वरन् एक मिशन है, इसलिए शिक्षक ''बाई डिफाल्ट'' न होकर ''बाई डिजाइन'' होना चाहिए। इससे पूर्व संगठन के अध्यक्ष डॉ. मधुर मोहन रंगा ने संगठन का परिचय दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. सोमकांत भोजक ने किया। महामंत्री द्वारा आभार व्यक्त किया गया। संगोष्ठी में लगभग 70 शिक्षक उपस्थित थे।

6. **अम्बेड़कर एवं प्रताप जयन्ती पर कार्यक्रम सम्पन्न** - 14 अप्रेल को संगठन द्वारा अजमेर में अम्बेड़कर जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। प्रात: 10 बजे संगठन के पदाधिकारियों ने बस स्टैण्ड स्थित अम्बेड़कर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके व्यक्तित्व एवं कार्यों का स्मरण किया। महाराणा प्रताप जयन्ती के अवसर पर 11 जून को राजकीय महाविद्यालय, अजमेर स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में इतिहास संकलन समिति अजयमेरु महानगर के अध्यक्ष डॉ. नवलकिशोर उपाध्याय ने महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व व कर्त्तत्व पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस महान देश भक्त के योगदान को हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिये। संगठन के अध्यक्ष डॉ. मधुर मोहन रंगा ने कहा कि यदि आज विश्व के मानचित्र पर भारत का अस्तित्व है तो इसका श्रेय महाराणा प्रताप को जाता है उन्होंने मुगल आक्रान्ताओं को परास्त कर राष्ट्रीय चेतना की लहर को अनवरत बनाये रखा। उन्होंने कहा कि प्रताप कुशल रणनीतिज्ञ एवं छापामार युद्ध के प्रणेता होने के साथ-साथ सामाजिक समरसता के अग्रदूत भी थे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. अजय शर्मा ने किया जबकि धन्यवाद डॉ. महेन्द्र गोखरु ने ज्ञापित किया। इस अवसर पर पूर्व प्राचार्य प्रो. शेरसिंह, डॉ. राधेश्याम अग्रवाल, डॉ. अनिल गुप्ता, डॉ. विमलचन्द शर्मा आदि सदस्य उपस्थित थे।

7. **विवेकानंद सार्द्ध शती कार्यक्रम** - भीलवाड़ा जिले के राजकीय व गैर राजकीय महाविद्यालयों के संयुक्त तत्वावधान में विवेकानंद सार्द्ध शती के अन्तर्गत व्याख्यान रखा गया। मुख्य वक्ता डॉ. श्याम सुन्दर भट्ट ने कहा कि स्वामीजी के शैक्षिक चिंतन से भारत के साथ साथ सम्पूर्ण विश्व को दिशा प्राप्त हो सकती है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व एवं कर्त्तत्व पर विचार व्यक्त करते हुए शिक्षकों से आह्वान किया कि स्वामीजी के चरित्र से स्वयं प्रेरणा ग्रहण कर विद्यार्थियों को उनके बताए मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित करें।

सूचनाएं

1. **गुरु वंदन कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह** - अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की 8-9 जून को जमशेदपुर में सम्पन्न राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के निर्णयानुसार इस सत्र् से गुरुपूर्णिमा (इस बार 22 जुलाई 2013) के अवसर पर इकाई स्तर पर गुरु वंदन कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। भारत में सदा ही गुरुजनों ने शिक्षा दीक्षा के माध्यम से राष्ट्र की उन्नति में सहभाग किया है। सौभाग्य से अतिप्राचीन काल से वर्तमान समय तक ऐसी श्रेष्ठ गुरु परम्परा के उदाहरण भारत में रहे हैं। गुरु पूर्णिमा

के पावन दिन ऐसी अनुकरणीय परम्पराओं का स्मरण कर वर्तमान चुनौतियों का सामना करने हेतु प्रेरणा प्राप्त करें, ऐसा इस आयोजन का उद्देश्य है। सभी इकाईयों से आग्रह है कि इस कार्यक्रम का प्रेरक आयोजन कर समाचार पत्रों में एवं महामंत्री को सूचना प्रेषित करें।

2. **सदस्यता अभियान** - अपना सदस्यता अभियान 1 से 15 जुलाई तक भली भांति सम्पन्न हुआ। सभी स्थानों से सदस्यता एकत्रीकरण के उत्साहजनक समाचार है। सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि सदस्यता का हिसाब 31 जुलाई तक पहुँचा देना है। यदि कोई शिक्षक सदस्यता हेतु सम्पर्क से छूट गया है तो 31 जुलाई से पूर्व तक उससे सदस्यता अवश्य ले लेनी है, 31 जुलाई के पश्चात् रुक्टा (रा.) की इस सत्र् की सदस्यता स्वीकार नहीं की जानी है।

3. **विभागीय सम्मेलन** - सितम्बर-अक्टूबर में एक साथ सभी विभागों के विभागीय सम्मेलन आयोजित किये जाने हैं। अपने विभाग के सम्मेलन की योजना सक्रिय कार्यकर्ताओं को अभी से कर लेनी चाहिए।

4. **प्रबोधनात्मक जनजागरण** - शैक्षिक महासंघ की योजना से इस वर्ष प्रबोधनात्मक जनजागरण हेतु ''शाश्वत जीवन मूल्य'' विषय तय किया गया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी अलग से प्रेषित की जाएगी।

5. **राष्ट्रीय संगोष्ठी** - शैक्षिक महासंघ के तत्वावधान में रुक्टा (रा.) द्वारा 'Regulatory Mechanism in Higher Education' विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जानी है। इस संबंध में भी सूचना आपको अलग से प्रेषित की जाएगी।

उत्तराखण्ड में हुई भीषण त्रासदी से देश का प्रत्येक नागरिक दु:खी हुआ है। रुक्टा (रा.) भी आपदा एवं दु:ख की घड़ी में देश के साथ है। संगठन के कई सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से अपनी सहायता पीड़ितों तक भेजी है। मुख्यमंत्री सहायता कोष में एक दिन का वेतन इस परमार्थ हेतु देने का आग्रह संगठन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा किया गया है। सरकार की तरफ से इस आग्रह को मानते हुए एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करने हेतु आदेश जारी कर दिये हैं। अर्थ से इस त्रासदी की भरपाई तो नहीं की जा सकती किन्तु ईश्वर की लीला के आगे हम सभी नतमस्तक है। संगठन की ओर से इस त्रासदी में दिवगंत हुए सभी तीर्थ यात्रियों की आत्मा की चिर शांति हेतु प्रार्थना है।

आभार।

भवदीय

(डॉ. नारायणलाल गुप्ता)
[महामंत्री]

20, चित्रकूट कॉलोनी,
माकड़वाली रोड़, अजमेर-305004

अमृत वचन

जिस संयम के द्वारा इच्छा-शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वह फलद्रायक होता है,वह शिक्षा कहलाती है।
- स्वामी विवेकानंद